निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1937 (श0)

(सं0 पटना 876) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2015

सं0 को0प्र0 / कम्प्यूटर–7 / 2010(खण्ड)–6815

वित्त विभाग

————————

संकल्प

4 अगस्त 2015

विषयः—बिहार राज्य में कोषागारों तथा वित्त विभाग के आधुनिकीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन (CFMS) योजना के कार्यान्वयन हेतु मनोनयन (Nomination) के आधार पर चयनित परामर्शी National Institute of Smart Governance (NISG) को पूर्व मे दिए गए दो stage के कार्य के अतिरिक्त बचे हुए दो stage हेतु रू. 60 लाख (सेवाकर अलग से) की अनुमानित लागत पर कार्य हेतु Consultant चयनित करने तथा CFMS परियोजना के कार्यान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव हेतु Nodal Agency के रूप में BSEDC को नामित करने के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा National e-Governance Plan के अंतर्गत मिशन मोड परियोजना के द्वारा राज्य के विभिन्न कोषागारों, वित्तीय प्रबंधन योजनाओं का आधुनिकीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अन्य राज्यों में भी भारत सरकार के मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत कोषागारों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है । वित्तीय वर्ष 2011–12 में भारत सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत लगभग रु. 11.40 करोड़ (ग्यारह करोड़ चालीस लाख रुपए) की राशि विमुक्त की गई थी।

2. पूर्व में प्रस्तावित Comprehensive Financial Management System, वर्तमान में कोषागारों को कम्प्युटरीकृत करने हेतु वित्त विभाग में Comprehensive Treasury Management Information System के रूप में जाना जाता है। यह सिस्टम वर्ष 2006 में ही लगायी गयी थी। यह लगभग आठ साल पुरानी हो चुकी है और इसकी संरचना में परिवर्तन की आवश्यकता है ।

3. दिनांक 28–03–2015 को मंत्रिपरिषद् से स्वीकृति प्राप्त कर NISG को वित्त विभाग के संकल्प संख्या–को0प्र0 / कम्प्यूटर–7 / 2010(खण्ड)–3332–वि०, दिनांक 31–03–2015 के द्वारा परियोजना के दो चरणो (i) Conceptualisation (ii) Architecture पर अध्ययन करके अपना मंतव्य देने का आदेश दिया गया था।

4. उक्त आदेश के आलोक में National Institute of Smart Governance ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है । इस संदर्भ में NISG ने विभिन्न बिन्दुओं पर अनुसंधान किया :–

(a) वर्तमान में कार्यरत CTMIS साफ्टवेयर का विस्तार से अध्ययन ।

(b) वित्त विभाग में कार्यरत पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा कुछ कोषागार पदाधिकारियों के IT Skill का आकलन,

(c) विभिन्न Stake holders का जैसे, FD, AG, बैंक तथा विभिन्न विभागों के साथ बैठक

(d) झारखंड में कार्यरत, NIC द्वारा कोषागारों के कम्प्युटराइजेशन हेतु बनाए गए साफ्टवेयर का अध्ययन

5. उन सभी बिन्दुओं पर अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात् NISG की टीम ने दिनांक 17–07–2015 को समर्पित IT Road Map Report द्वारा यह मत प्रस्तुत किया है कि "वित्त विभाग के कोषागारों में वर्तमान में कार्यरत CTMIS साफ्टवेयर के स्थान पर नए Comprehensive Financial Management System (CFMS) लागू किया जाय। इसके लिए नए सिरे से RFP प्रकाशित किया जाय और System Integrator का चयन किया जाय।'' ऐसा होने पर बिहार में एक सुदृढ़ Financial Management system लागू की जा सकेगी जो कि real time decision support system, trend analysis and projection आदि कार्य में काफी सहायक होगी। उक्त प्रतिवेदन को Bihar State Electronics Development Corporation Ltd., Patna (BSEDC) द्वारा भी इसकी समीक्षा करा ली गयी है।

इस परिस्थिति में NISG को उपरोक्त परियोजना के System Integrator (SI) का अंतिम चयन तक बचे हुए अन्य दो phase यथा–

Stage 3: Preparation of RFP on recommendation on setting up of PMU

I. Preparation of RFP - with deliverable "Request for proposal for implementation, operations and maintenance of Bihar – CFMS"

II. Recommendation on setting up of PMU in BSEDC under the overall supervision of Finance Department, Government of Bihar during the implementation and operation and maintenance phase of CFMS – with deliverable ***"PMU-monthly reports"***

Stage 4: Support till signing of contract with successful bidder

I. Assistance in conducting pre-bid meeting – with deliverable "Minute of meeting of pre-bid meeting on Bihar –CFMS RFP"

II. Assistance in bid evaluation – with deliverable "Bid evaluation report for Bihar CFMS RFP"

III. Support in contract finalization with the successful bidder

का कार्य भी Nomination के आधार पर सौंपा जाना है। इस कार्य हेतु NISG ने रू. 60 (साठ) लाख रूपये (सेवाकर अलग से) का प्रस्ताव दिया है।

6. राज्य क्रय संस्था BSEDC, बिहार वित्तीय नियमावली के 129 के अंतर्गत सभी प्रकार के हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर हेतु राज्य क्रय संगठन नामित है। NISG द्वारा दिए गए RFP के आधार पर CFMS परियोजना का कार्यान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव का काम BSEDC को Nomination के आधार पर दिया जा सकता है। इस परियोजना से संबंधित हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर तथा अन्य सामग्रियों की खरीदगी BSEDC करेगा, जिसमें वित्त विभाग, बिहार सरकार का स्वामित्व होगा। परन्तु कोषागारों के दैनन्दिक कार्यों में आवश्यक सामग्री जैसे–जेनरेटर के लिए डीजल, प्रिंटर के लिए कार्टेज, लेखन सामग्री आदि का क्रय स्थानीय स्तर पर ही किया जायेगा।

BSEDC को देय सेवा शुल्क वित्त विभाग द्वारा अलग से भुगतान किया जायेगा। BSEDC द्वारा इस परियोजना हेतु हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीदगी पर या अन्य किसी एजेंसी से अलग से कोई सेवा शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7. नए System Integrator का सफलतापूर्वक चयन करने के बाद अनुमानित दिनांक 01–04–16 से प्रारंभ होंने वाले वित्तीय वर्ष तक नए CFMS को भी आंरभ करने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। उक्त कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा की तालिका इस प्रकार होगी :–

Sl No	Task / stage	Timeline
1.	Preparation and floating of RFP	5th August 2015
2.	Pre-Bid meeting	Will be decided by BSEDC
3.	Release of clarification to pre-bid queries	Will be decided by BSEDC
4.	Receipt of responses to RFP from bidders	By mid of October 2015

5.	Bid evaluation	By mid of November 2015
6.	Signing of contract between Finance Department, Govt. of Bihar and successful bidder	By end of November 2015
7.	Implementation and Go-live of system	1st April 2016

उक्त कार्य हेतु NISG द्वारा कुल राशि रु. 94.90 लाख रुपए (सेवाकर अलग से) की माँग की गई थी। वित्त विभाग एवं NISG के बीच हुई वार्ता के उपरांत उक्त कार्य हेतु रू. 60 लाख रूपये (सेवाकर अलग से) पर सहमति बनी है।

8. उक्त के आलोक में राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाता है :–

(क) बिहार राज्य में कोषागारों तथा वित्त विभाग के आधुनिकीकरण एवं वित्तीय प्रबंधन (CFMS) योजना के कार्यान्वयन हेतु मनोनयन (Nomination) के आधार पर National Institute of Smart Governance (NISG) को परामर्शी के रूप में रू. 60 लाख (सेवाकर अलग से) की अनुमानित लागत पर Two stage(Stage 3: Preparation of RFP on recommendation on setting up of PMU and Stage 4: Support till signing of contract with successful bidder) के कार्य हेतु Consultant चयनित किया जाता है।

(ख) प्रस्तावित CFMS परियोजना का कार्यान्वयन, संचालन एवं रख–रखाव हेतु Nodal Agency के रूप में BSEDC को नामित किया जाता है।

आदेश-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
एच० आर० श्रीनिवास,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 876-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in